Sector		Investment Required (Rs. crores)
B. *Fisheries—Harbour Development Projects*	..	52.02
C. *Industries*		
1. Traditional Industries	..	21.00
2. Large and Medium Industries		16.55
3. Small Industries		16.31
D. *Employment for Special Groups*		
1. Harijan Development Corporation		10.00
2. Post Graduates	..	1.00
3. Agricultural Graduates		0.25
E. *Education*		
1. Abolition of shift in III standard	..	2.10
2. Buildings and equipment for Government Schools	..	1.50
3. Provision of Nursery School Facilities	..	1.00
	TOTAL	186.88

वैज्ञानिकों के लिये सेवा की असंतोषप्रद शर्तें

*364. श्री पीताम्बर दास :
डा० भाई महावीर :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री डी० के० पटेल :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री ओउम् प्रकाश त्यागी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान कितने भारतीय वैज्ञानिक विदेश चले गये हैं या उन्होंने आत्महत्या कर ली है ; और

(ख) इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

†[UNSATISFACTORY CONDITIONS OF SERVICE FOR SCIENTISTS

*364. SHRI PITAMBER DAS :
DR. BHAI MAHAVIR :
SHRI J. P. YADAV :
SHRI D. K. PATEL :
SHRI PREM MANOHAR :
SHRI O. P. TYAGI :

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) the number of Indian scientists who have gone abroad or committed suicide during the last three years ; and

(b) the reaction of Government thereto, and the action taken or proposed to be taken in this regard ?]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) कोई औपचारिक सूचना

† [ ] English translation.

उपलब्ध नहीं है। फिर भी, गत तीन वर्षों में लगभग 2,700 भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी-विदों, इंजीनियरों एवं चिकित्सकों ने अपने आने को राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग में पंजीकृत करवाया है, जिसमें पंजीकरण स्वैच्छिक है।

गत तीन वर्षों के दौरान, डा० विनोद एच० शाह, वरिष्ठ शस्य वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई० ए० आर० आई०), नई दिल्ली की आत्महत्या से सम्बन्धित सूचना के अतिरिक्त, सरकार के पास अन्य कोई आत्महत्या सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) विभिन्न अनुसंधान संगठन अपनी भर्ती, पदोन्नति आदि से सम्बन्धित कर्मचारी नीतियों की पुनरावृत्ति करने के लिये प्रस्तावों की रूप-रेखा तैयार कर रहे हैं।

वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के लिये रोजगार सम्बन्धी सुअवसरों में वृद्धि के लिए कुछ उपाय किये गये हैं। तत्सम्बन्धी एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए नौकरी की सुविधा में सुधार लाने के लिए जो कुछ उपाय किए गये, वे नीचे दिये गये हैं :—

(1) वैज्ञानिकों को योग्यता पर पदोन्नति तथा योग्यता पदोन्नति योजना के अन्तर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती है।

(2) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक से ऊपर वैज्ञानिक 'सी' के स्तर तक (700 से 1,250 रु०) अगले ऊंचे पद के लिये पांच वर्षों में एक बार वैज्ञानिकों की योग्यता आंकी जाती है।

(3) देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालय के बाहर भी शिक्षावृत्तियां दी जाती हैं ?

(4) वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए सहायता-अनुदान देना।

(5) विश्वविद्यालयों की चौथी योजना की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विशिष्टाओं/विश्वविद्यालय विभागों में वरिष्ठ कर्मचारियों के पद निमित करने के वास्ते सहायता देने के लिये सहमत हो गया है। प्रयोगशाला के और विकास तथा विशिष्ट उपस्कर की खरीद समेत, अन्य सुविधाओं के लिए भी व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार, अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कार्य अनुसंधान के लिए अवसर उपलब्ध किए जा रहे हैं।

(6) विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च अध्ययन केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सावधानी से चुने गए विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विभागों को विशेष सहायता प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिये उपयुक्त परिस्थितियों और सुविधाओं की व्यवस्था करना और केन्द्रों में कार्य करने के लिये योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करना है।

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में भी सुधार किया है जिनसे उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के आकर्षित होने तथा वहां बने रहने की सम्भावना है।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षण व्यवसाय के प्रति उच्च बौद्धिक योग्यता वाले पुरुषों और स्त्रियों को काफी अनुपात में आकर्षित करने के महत्व पर निरन्तर बल देता रहा है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमान सुधारने के अलावा, शिक्षण व्यवसाय में अनिवार्य सुविधाओं तथा प्रेरणाओं की व्यवस्था करने के प्रयत्न किए गये हैं। अनुसंधान तथा विद्वत्तापूर्ण कार्य, अध्यापकों के विनिमय, देश में उच्च अध्ययन अनुसंधान के केन्द्रों का दौरा करने के लिये यात्रा

अनुदानों के लिये तथा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिये, स्टाफ क्वार्टरों तथा अध्यापकों के छात्रावास आदि के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(9) भारत सरकार ने बेरोजगारी का मूल्यांकन करने और उसके उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक 'बेरोजगार सम्बन्धी समिति' नियुक्त की है। रोजगार के लिए अंशकालीन उपायों पर समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है।

(10) शिक्षित बेरोजगारों को चौथी योजना में रोजगार प्रदान करने के लिये 50 करोड़ रुपये की एक राशि रखी गयी है। इसमें से 20 करोड़ रुपये इसी वर्ष के बजट में आवंटित किये गये हैं।

(11) योजना आयोग ने 27 करोड़ रुपये की एक धनराशि निर्धारित की है। यह राशि राज्य सरकारों को रोजगार के विशेष कार्यक्रम जुटाने के लिये आवंटित की गयी है। इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को भी 27 करोड़ रुपये और लगाने होंगे।

(12) उद्योगी बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंक भी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

(13) वैज्ञानिक पूल, अनुसंधान छात्र-वृत्तियां, अधिसंख्यक पदों पर नियुक्तियां जैसी योजनायें वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की सहायतार्थ कार्यरत हैं।

(14) योजना आयोग और राज्य सरकारें भी बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन कर रही हैं।

t[THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRA-MANIAM) : (a) No precise information is available. However, (luring the last three years about 2,700 Indian Scientists, Technologists, Engineers and Doctors enrolled them-selves in the Indians Abroad Section of the National Register in which registration is voluntary.

Government have no information of any case of suicide during the last three years except that of Dr. Vinod H. Shah, Senior Agronomist, Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi,

(b) Various research organisations are drawing up proposals for revising their personnel policies regarding recruitment, promotion, etc.

Some of the measures taken to improve employment opportunities for Scientists and Engineers arc given in the Statement laid on the Table of the House.

STATEMENT

Some of the measures taken to improve employment opportunities for scientists and engineers are given below :

(1) Scientists are given merit promotion and advance increments under the Merit Promotion Scheme.

(2) Merit of scientists from senior Scientific Assistant onwards to the level of Scientist 'C (Rs. 700—1250) is assessed once in five Years for promotion to the next higher post.

(3) Fellowships are provided in the National Laboratories / Institutes and outside research institutions and Universities to encourage scientific talent in the country.

(4) Grant-in-aid to Scientists to carry out research.'

(5) As a result of the assessment of Fourth Plan developmental needs of the universities, the University Grants Commission (UGC) has agreed to provide assistance for the creation of senior staff positions in various specialities/ university departments. Provision has also been made for further development of laboratory and other facilities including the purchase of specialised equipment. Opportunities are thus being made available for advanced work /research in various fields for scholars and scientists having the requisite qualifications.

■f[ ] English translation.

(6) The UGC has been providing special assistance to carefully selected university/university departments to lunation as Centres of Advanced Study in specific fields. The aim is to provide suitable conditions and facilities for advanced studies and research, and to attract competent personnel for work at the Centres.

(7) The UGC has also brought about improvement in the salary scales of teachers of universities and colleges which are expected to attract and retain the services of highly qualified people.

(8) The UGC has all along emphasised the importance of attracting a reason able proportion of our men and women of high intellectual ability to the teaching profession. Besides improving the salary scales of teachers in the Universities and colleges, efforts have been made to provide essential amen ities and incentives for the teaching profession. Financial assistance is be ing provided for research and learned work, exchange of teachers, travel grants for visiting centres of research in advanced study in the country and for attending international conferences abroad, construction of staff quarters and Teachers' hostels etc.

(9) The Government of India have appointed a 'Committee on Unemployment" to assess the extent of unemployment and to suggest remedial measures. The Committee have submitted an interim report on short-term measures for employment.

(10) The Government have allocated a sum of Rs 50 crores in the 4th Plan for employment of educated unemployed, of which, an amount of Rs 20 crores has been allocated in this year's budget.

(11) An amount of Rs 27 crores has been earmarked by the Planning Commission for allocation to State Governments for formulating special employment programmes for which the States will have to contribute another 27 crores.

(12) Financial help is also rendered to enterprising unemployed persons by Nationalised Banks.

(13) The scheme like Scientists' Pool, Research Fellowships, Supernumerary appointments are in operation to help the Scientific and Technical Personnel.

(14) Tae Planning Commission and the Slate Governments are also considering the problem of unemployment.]

VICTIMISATION OF DELHI TELEPHONE STAFF

*365. SHRI K. C PANDA :
SHRI M. K. MOHTA :
SHRI CHANDRAMOULI JAGARLAMUDI : SHRI BHOLA PRASAD :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Administration Staff Union of the Delhi Telephones Office have complained to Government that they were being victimised by certain officers on account of public complaints for the defective bill accounting system ;

(b) if so, the reaction of Government in this regard ;

(c) the nature of the various complaints received from the subscribers about the defective billing, and the action, if any, taken on those complaints ; and

(d) the number of complaints still to be disposed of by the Delhi Telephones ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b) Yes Sir, but the charge of victimisation contained therein is not correct.

(c) Complaints fram subscribers generally fall under the following categories :—

(i) Alleged excessive metering of local calls.

(ii) Bills for accessories allegedly not provided.

(iii) Bills for trunk calls allegedly not made by the subscribers. (iv) Incorrect valuation of trunk calls arising from alleged incorrect timing or classification of calls.